

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely : -

"(3) Architect/ Structural Engineer duly registered by the Authority having jurisdiction may be authorised to issue the building permission on the plots measuring up to 300 sq. meter after getting approval of the Director, town and country planning :

Provided that such permission cannot be issued to the colonisers who intend to sale the plot/ building.

Provided further that the competent Authority shall not give the power to issue building permission to such Architect/Structural Engineer who does not fulfil the norms provided in rule 26-A and 26-B and do not possess minimum 10 years experience."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 2016-1264-2019-पचास-2-

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020

अधिसूचना

मध्यप्रदेश लाइली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 29 सन् 2018) की धारा 9 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में लाइली लक्ष्मी योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) योजना नियम, 2020 है।
- (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 29 सन् 2018);
- (ख) "आंगनवाड़ी केन्द्र" से अभिप्रेत है, किसी जिले के ग्राम अथवा वार्ड में अवस्थित समेकित बाल विकास परियोजना के अधीन संचालित केन्द्र, जहां बालिका को रजिस्ट्रीकृत किया गया है;
- (ग) "आंगनवाड़ी कार्यकर्ता" से अभिप्रेत है, संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र में नियुक्त कोई व्यक्ति, जो ग्राम/वार्ड स्तर पर अपने सर्वेक्षण क्षेत्र में योजना का आवेदन प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा अधिकृत किया गया हो;
- (घ) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है, महिला एवं बाल विकास विभाग का जिला कार्यक्रम अधिकारी, जो हितग्राही बालिका के पक्ष में जमा एवं देय का राशि का लेखा-जोखा संधारित करेगा;
- (ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट कोई प्राधिकृत अधिकारी, जो महिला एवं बाल विकास विभाग का बाल विकास परियोजना अधिकारी होगा;
- (च) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (छ) "पंजीयन केन्द्र का भारसाधक अधिकारी" से अभिप्रेत है, लोक सेवा गारंटी

अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के अधीन लोक सेवा केन्द्र का भारसाधक अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए हितग्राही का आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ;

- (ज) "भारसाधक व्यक्ति" से अभिप्रेत है, बाल देखरेख संस्थाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ;
- (झ) "हितग्राहियों का रजिस्टर" से अभिप्रेत है, हितग्राहियों का ऐसा रजिस्टर, जिसमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हितग्राहियों के नाम प्रारूप-तीन में पंजीकृत तथा संधारित किए जाते हैं;
- (ञ) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;
- (ट) "पर्यवेक्षक" से अभिप्रेत है, संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र का पर्यवेक्षण करने वाला व्यक्ति;
- (ठ) "योजना" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथा विनिर्दिष्ट लाडली लक्ष्मी योजना।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. योजना की पात्रता.— कोई बालिका, जो योजना के अधीन हितग्राही के रूप में पंजीकृत है या पंजीकृत की गई है, अधिनियम की धारा 5 में यथाविनिर्दिष्ट लाभों के लिए पात्र होगी।

4. हितग्राही के रूप में पंजीकरण के लिए हकदार.—

(1) ऐसे माता-पिता योजना में हितग्राही के रूप में अपनी बालिका का नाम पंजीकृत कराने के लिए पात्र होंगे, यदि —

(क) बालिका, जिसके माता-पिता मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार होगी;

(ख) रजिस्ट्रीकरण के समय माता-पिता आयकर दाता नहीं हैं :

परंतु यदि रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् या तो माता या पिता या दोनों आयकर दाता हो जाते हैं, तो भी बालिका योजना के अधीन निरंतर लाभ प्राप्त करती रहेगी;

(ग) प्रथम जन्मी बालिका योजना के लाभों की हकदार होगी, चाहे उसके माता-पिता ने नियोजन अपनाया हो अथवा नहीं, परंतु दूसरी बालिका के पंजीकरण के लिए परिवार नियोजन अपनाए जाने की शर्त अनिवार्य होगी और प्रथम प्रसव में दो या दो से अधिक बालिकाओं के जन्म की दशा में, सभी बालिकाएं पात्र होंगी।

(घ) बालिका को नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र में नामांकित किया जाना चाहिए।

(2) यदि हितग्राही देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली सीएनसीपी बालिका है, तो हितग्राही के लिए कोई पूर्वोक्त शर्त लागू नहीं होगी।

(3) विशेष प्रकरणों में हितग्राही पंजीकरण हेतु पात्रता.—

- (1) यदि किसी परिवार में अधिकतम दो बच्चे हैं और माता-पिता में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार नियोजन अपनाए जाने की शर्त लागू नहीं होगी, किन्तु मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना एक पूर्व अपेक्षित कसौटी होगी। ऐसे प्रकरणों में, 05 वर्ष की उम्र होने तक योजना में बालिका का पंजीयन किया जा सकेगा।
- 4 (2) यदि किसी परिवार ने किसी बालिका को विधिक रूप से दत्तक लिया है तो बालिका प्रथम बालिका के रूप में योजना के लाभों की हकदार होगी, परंतु परिवार को, बालिका को दत्तक लेने या उत्तराधिकार के एक वर्ष के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन करना चाहिए।
- (3) यदि माता-पिता या उनमें से किसी ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से एक वर्ष के भीतर योजना के अधीन पंजीयन के लिए आवेदन नहीं किया है, तो ऐसे माता-पिता बालिका के जन्म से दो वर्ष के भीतर सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी ऐसे आवेदनों को प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष स्वीकृति अथवा अस्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा।
- (4) राज्य सरकार को कालातीत प्रकरणों को मंजूरी देने की शक्ति होगी।
- (5) जहां एक बालक अथवा बालिका के पश्चात्, किसी परिवार में जुड़वा बालिकाएं जन्म लेती हैं, तो दोनों बालिकाएं योजना के अधीन लाभों के लिए पात्र होंगी।
- (6) महिला कैदी, जो किसी भी कारण से जेल में परिरुद्ध है और बालिका को जेल में जन्म देती है, की बालिका भी योजना के अधीन लाभों की हकदार होगी।
- (7) किसी बलात्संग पीड़िता द्वारा जन्मी बालिका भी योजना के अधीन लाभ के लिए हकदार होगी।

5. पंजीयन हेतु आवेदन.-

- (1) माता-पिता बालिका के जन्म अथवा दत्तक लिए जाने के एक वर्ष के भीतर पंजीयन केन्द्र के भारसाधक अधिकारी को प्रारूप-एक में, दो प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करेंगे:

परंतु प्रारूप एक में आवेदन लोक सेवा केन्द्र पर या विभाग की लाइली लक्ष्मी योजना वेबसाइट (www.ladililaxmi.mp.gov.in) के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।

- (2) योजना के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने समय निम्नलिखित जानकारी दिया जाना अपेक्षित होगा:-

- (क) माता-पिता के मूल निवासी होने का प्रमाण;
- (ख) बालिका का जन्म प्रमाण-पत्र;
- (ग) दूसरे बच्चे की दशा में परिवार नियोजन अपनाए जाने का विश्वसनीय प्रमाण;
- (घ) आंगनवाड़ी केन्द्र में नामांकन का प्रमाण;
- (ङ) आयकरदाता न होने के संबंध में स्वयं का कथन;
- (च) अनाथालय में निवास का प्रमाण;
- (छ) दत्तक लेने वाले माता-पिता द्वारा दत्तक ली गई बालिका का प्रमाण।

- (3) जेल या अनाथालय या बाल देखरेख संस्था के प्रभारी व्यक्ति को ऐसे जेल या बाल देखरेख संस्था में बालिका प्रवेश/भर्ती होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर किंतु उसके पांच वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्व, हितग्राही बालिका के पंजीयन हेतु आवेदन करना होगा।

6. पंजीकरण प्रक्रिया.—

- (1) आवेदन की प्राप्ति पर, केन्द्र का भारसाधक अधिकारी अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आवेदन की अन्तर्वस्तुओं का सत्यापन करेगा, उसे पंजी में दर्ज करेगा तथा अनुक्रमांक प्रदान करेगा और दूसरी प्रति माता-पिता को वापस की जाएगी। उसके पश्चात् वह उसे आश्वासन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।
- (2) आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी या तो प्ररूप-दो में आश्वासन प्रमाण-पत्र जारी करेगा अथवा आवेदन को लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों सहित निरस्त करेगा और बालिका के माता-पिता को सूचित करेगा। सक्षम प्राधिकारी, आवेदन का निपटारा उसे प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर करेगा।

सक्षम प्राधिकारी, आश्वासन प्रमाण-पत्र जारी करने की संख्या तथा पर्याप्त कारणों से उसके द्वारा नामंजूर किए गए आवेदनों की संख्या अन्तर्विष्ट करते हुए प्राधिकृत अधिकारी को दो माह की कालावधि के भीतर प्ररूप दो (क) में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

- (3) आश्वासन प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात्, सरकार की ओर से ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तीस हजार रूपए की राशि जमा की जाएगी जो महिला बाल विकास द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा। ऐसा अधिकारी समुचित लेखा संधारित करेगा और इसकी रिपोर्ट प्रत्येक कलेक्टर के माध्यम से आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजी जाएगी।
- (4) हितग्राहियों का रजिस्टर संधारित किया जाएगा और प्ररूप-तीन में दिए गए प्रपत्र में प्राधिकृत अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। इसके अलावा, इस संबंध में जानकारी योजना की वेबसाइट www.ladlilaxmi.mp.gov.in पर भी संधारित की जाएगी।

7. अपील.—

- (1) यदि आवेदन निरस्त कर दिया जाता है अथवा समय-सीमा में नहीं किया जाता है, तो निम्नानुसार अपील प्रस्तुत की जा सकेगी—

1. प्रथम अपील — जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रथम अपील अधिकारी होगा। अपील निराकृत करने के लिए समय-सीमा 15 कार्य दिवस होगी।
2. द्वितीय अपील— प्रथम अपीली अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

8. पंजीकरण निरस्त किया जाना.—

- (1) योजना में पंजीयन के उपरांत यदि आवेदन में की अंतर्वस्तुएं जांच में असत्य या गलत पाई जाती हैं तो ऐसे पंजीयन को सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा निरस्तीकरण के पश्चात् समस्त लाभ सरकार को समपहृत हो गये, समझे जाएंगे। परन्तु पंजीयन निरस्त करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना आवश्यक होगा।
- (2) पंजीकृत बालिका का बाल विवाह होने पर योजना में पंजीकरण स्वमेव निरस्त माना जाएगा तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी।
- (3) पंजीकृत बालिका की मृत्यु होने पर समस्त लाभ राज्य सरकार को अंतरित हो गए समझे जाएंगे।
- (4) बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत् ऐसी बालिकाएं जो लाडली लक्ष्मी योजना के अधीन पंजीकृत हैं, का दत्तक ग्रहण के विदेश अथवा मध्यप्रदेश से बाहर अन्य प्रदेशों के मूल निवासी अभिभावकों द्वारा किया जाता है, जो इन बालिकाओं का लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीयन न्यायालय के आदेश की तारीख से 2 वर्ष के पश्चात् निरस्त किया जाएगा। परन्तु प्रदेश के मूल निवासी परिवार द्वारा दत्तक ली गई बालिकाओं को योजना का लाभ जारी रहेगा।
- (5) निरस्त प्रकरणों संबंधित समस्त दस्तावेज योजना के पोर्टल <http://ladlilaxmi.mp.gov.in> पर संधारित किए जाएंगे।

9. लाभों की हकदारी.—

- (1) योजना के अधीन पंजीकृत प्रत्येक बालिका रूपए 1,18,000/— (एक लाख अठारह हजार रूपए) मात्र की राशि की निम्नानुसार हकदार होगी:—
 - (एक) कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने के समय रूपए 2000/—(दो हजार रूपए) मात्र
 - (दो) कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के समय रूपए 4000/—(चार हजार रूपए) मात्र
 - (तीन) कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने के समय रूपए 6000/—(छह हजार रूपए) मात्र
 - (चार) कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने के समय रूपए 6000/—(छह हजार रूपए) मात्र
 - (पांच) 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रूपए 1,00,000/—(एक लाख रूपए) मात्र:

परन्तु खण्ड एक से चार के अधीन लाभ प्राप्त करते समय पूर्व कक्षा की अंक-सूची के साथ अध्ययनस्त कक्षा में बालिका के प्रवेश की जानकारी आवश्यक रूप से संगृहीत प्रस्तुत की जाएगी :

परन्तु यह और कि खण्ड पांच के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका को कक्षा 12वीं की परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, तथा 12वीं की अंकसूची प्रस्तुत की जाना होगी:

परन्तु यह और भी कि विवाहित हितग्राही की दशा में विवाह रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) योजना के लिए भुगतान मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना फंड बजट, जैसा कि महिला और बाल विकास विभाग द्वारा हितग्राही के लिए अलग से रखा गया है में किया जाएगा।

- (3) आशवासन प्रमाण पत्र में कथित राशि ई-भुगतान के माध्यम से केवल हितग्राही के खाते में भुगतान की जाएगी।
 - (4) यदि बालिका विहित पात्रता शर्त पूरा नहीं करती है या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो समस्त लाभ राज्य सरकार को समपहृत हो गए समझे जाएंगे।
 - (5) अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन हितग्राही को प्रोद्भूत धन संबंधी लाभ स्थायी प्रकृति के होंगे और उन्हें वसूल नहीं किया जाएगा, परंतु अंतिम लाभ अधिनियम में विनिर्दिष्ट बालिका की पात्रता पर आधारित होगा।
 - (6) इस योजना के अधीन, हितग्राही की माता संरक्षक होगी और माता की मृत्यु की दशा में, पिता संरक्षक होगा और यदि माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो उसका विधिक संरक्षक कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो डिप्टी कलेक्टर या जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा और अनाथालय अथवा बाल देखरेख संस्था की दशा में, अधीक्षक, विधिक संरक्षक होगा, जहां उस अनाथ बालिका को प्रवेश दिया गया है।
 - (7) पात्र अभ्यर्थियों को विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- 10. लाडली लक्ष्मी योजना निधि का संधारण.—**
- (1) राज्य सरकार एक निधि गठित तथा संधारित करेगी, जो कि मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि के रूप में जानी जाएगी, जो हितग्राही को धन संबंधी लाभ संवितरित करने के लिए उपयोग की जाएगी।
 - (2) निधि का गठन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा.—
 (एक) प्रत्येक हितग्राही के लिए उसके पंजीयन के पश्चात निधि में राज्य शासन की ओर से, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राशि रूपए 30,000/- (तीस हजार रूपए) की राशि जमा की जाएगी ; तथा
 (दो) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जमा की गई, डाक विभाग द्वारा जारी, राष्ट्रीय बचत पत्र की ब्याज सहित परिपक्व राशि, यदि कोई हो;
 (तीन) इसके आलावा, हितग्राहियों के दावों का निपटारा करने हेतु निधि में आवश्यकता होने पर राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी तथा निधि में अंतरित की जाएगी।
 - (3) प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति में सचिव, वित्त विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त सदस्य होंगे। समिति में आयुक्त, महिला एवं बाल विकास सदस्य सचिव होंगे। फंड (निधि) की समीक्षा करने के लिए समिति सम्मिलन का संचालन करेगी।
- 11. हितग्राहियों के अभिलेख का संधारण.—**
- (1) योजना के अधीन हितग्राहियों से संबंधित एक रजिस्टर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित रूप से संधारित किया जाएगा और इस हेतु तैयार किए गए रजिस्टर में

हितग्राहियों के समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। इसके अलावा, समस्त दस्तावेज योजना के पोर्टल www.ladlilaxmi.mp.gov.in पर संधारित किए जाएंगे।

- (2) जब कभी हितग्राही को कोई आश्वासन प्रमाण-पत्र जारी किया जाए, तो उसके ब्यौरे दर्ज किए जाएंगे और आश्वासन प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी। आश्वासन प्रमाण पत्र योजना के पोर्टल www.ladlilaxmi.mp.gov.in से डाऊनलोड किया जा सकता है।
- (3) प्रत्येक हितग्राही को योजना के पोर्टल www.ladlilaxmi.mp.gov.in से एक नामांकन क्रमांक प्रदान किया जाएगा और उसकी प्रविष्टि इस प्रयोजन हेतु रखे गए रजिस्टर में की जाएगी।
- (4) जब कभी भी हितग्राही को कोई भुगतान किया जाए, उसकी प्रविष्टि रजिस्टर तथा योजना पोर्टल www.ladlilaxmi.mp.gov.in में हितग्राही के नाम के सामने उस तारीख के साथ अभिलिखित की जानी चाहिए, जिसको कि ई-पेमेंट के द्वारा रकम संदत्त की गई है।

12. अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) तथा मूल्यांकन.-

(1) जिला स्तर पर.-

- (क) प्राधिकृत अधिकारी (जिला कार्यक्रम अधिकारी), महिला एवं बाल विकास विभाग अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) के लिए उत्तरदायी होगा। यदि आवश्यक हो तो, वह योजना के अधीन ऐसे सभी मामलों का मूल्यांकन भी करेगा, जो कि सक्षम प्राधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी) द्वारा विनिश्चय किए गए हों तथा वह कलेक्टर को समय-समय पर, रिपोर्ट भी प्रेषित करेगा।
- (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् कलेक्टर, रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी योजना के संबंध में कठिनाइयों सुझावों एवं अनुशंसाओं (यदि कोई हों) को आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग को रिपोर्ट करेंगे।
- (ग) अधिनियम की धारा 8 के अधीन जिला स्तर पर हितग्राही के पंजीयन/लाभ के संबंध में यदि कोई विवाद उद्भूत होता है तो जिला कलेक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) संभाग स्तर पर.-

संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने अधीनस्थ जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के समय-समय पर संचालित निरीक्षणों में योजना संबंधी अभिलेखों का अवलोकरण करेंगे। साथ ही वह योजना क्रियान्वयन तथा अभिलेख संधारण के संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु निर्देश दे सकेंगे।

(3) राज्य स्तर पर.-

- (क) यदि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति पाई जाती है, तो विसंगति दूर करने के लिए विभाग का प्रमुख राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा भेजेगा।
- (ख) राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में किसी विवाद या विसंगति के उद्भूत होने की दशा में विभाग प्रमुख, महिला एवं बाल विकास विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

13. राज्य सरकार द्वारा निदेश.-

- (1) राज्य सरकार, अधिनियम तथा नियमों के अधीन बनाई गई योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जैसे कि वह उचित समझे।
- (2) योजना के अधीन हितग्राही के रूप में 1 अप्रैल, 2007 से इस अधिनियम के प्रारंभ होने की कालावधि के दौरान पंजीकृत समस्त बालिकाओं के लिए वर्षानुवर्ष बजट में उपबंध करके निधि पृथक् रूप से रखी जाएगी।

14. कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण.-

समस्त कार्यवाहियां, जो 01 अप्रैल, 2007 से शुरू होकर इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रारंभ होने तक वर्तमान में प्रचलित राज्य सरकार की मध्यप्रदेश लाइली लक्ष्मी योजना से संबंधित प्रशासनिक आदेशों के अधीन हैं, अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिमान्य समझी जाएंगी :

परंतु इन नियमों की अधिसूचना के पूर्व लाइली लक्ष्मी योजना के अधीन की गई कोई कार्रवाई या जारी किया गया कोई आदेश, जहां तक कि वह अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई है या जारी किया गया है।

15. अधिनियम तथा नियमों का अपालन .-

यदि कोई अधिकारी/संस्था या सांविधिक निकाय आदि जो पंजीयन और योजना के धनीय तथा अन्य लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार, यथोचित जांच के पश्चात् ऐसे अधिकारी/संस्था या सांविधिक निकाय आदि, जो अधिनियम के अधीन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है या जिसके बारे में उपेक्षा किया जाना पाया जाता है, के विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगी।

16. सूचना, शिक्षा एवं संचार.-

जन समुदाय के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए निश्चित अन्तराल पर नुक्कड़ नाटक, नारे लेखन, ब्रोशर, पोस्टर, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के माध्यम से राज्य शासन द्वारा, अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी।

17. बालिका की सहमति पर, उसे स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जा सके। इसके लिए लाइली लक्ष्मी योजना के हितग्राही द्वारा 21 वर्ष में प्राप्त की जाने वाली राशि का उपयोग आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं या बैंक लोन में मार्जिन मनी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आर्थिक रूप से सशक्त योजना के अधीन पंजीकृत बालिका को आर्थिक बोझ समझने की मानसिकता एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगी। लाइली लक्ष्मी योजना का मूल उद्देश्य बालिका को पढ़ने के समान अवसर प्रदान करना तथा आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

18. सामाजिक अंकेक्षण.-

अधिनियम के अधीन वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार स्थानीय निकाय एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कराएगी।

सामाजिक अंकेक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं से मिलकर बनेगा:-

1. लाइली लक्ष्मी योजना से समाज में बेटियों के प्रति मानसिकता में परिवर्तन।
2. लिंगानुपात में बढ़ोत्तरी।
3. परिवार द्वारा परिवार नियोजन अपनाना।
4. कन्या भ्रूण हत्या एवं बालिका के जन्म के पश्चात् हत्या को समाप्त करना।
5. बालिकाओं के शाला नामांकन अनुपात को बढ़ाना।
6. उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाना।
7. दहेज प्रथा की समप्ति।
8. बालिकाओं का आर्थिक संशक्तिकरण, अर्थात् कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना।

प्रारूप-एक
लाड़ली लक्ष्मी योजना
(नियम 3) तथा नियम 4(1) देखिए)
(हितग्राही के पंजीयन प्रारूप दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

लाड़ली लक्ष्मी योजना के अधीन हितग्राही के रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन प्रारूप (माता-पिता/विधिक संरक्षक/अधीक्षक/शिशु संरक्षण संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा भरा जाए)

प्रति,

प्रभारी अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण केन्द्र
सक्षम प्राधिकारी,
खण्ड/एकीकृत बाल विकास परियोजना
तहसील

जिला

मध्यप्रदेश

माता/पिता के साथ
बालिका का हाल ही का
फोटो चिपकाएं

महोदय,

मैं लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राही के रूप में मेरी पुत्री का नाम पंजीकृत करने की वांछा करता हूँ, ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

- 1 - बालिका का नाम :
- 2 - माता का नाम तथा आयु :
- 3 - पिता का नाम तथा आयु :
- 4 - व्यवसाय तथा परिवार की वार्षिक आय :
- 5 - पिन कोड तथा मोबाईल नम्बर सहित निवास का पता :
- 6 - (एक) बालिका की जन्म तारीख (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) -
(दो) वह दिनांक जिसको बालिका जेल/बाल संरक्षण संस्था में प्रवेशित हुई
(जेल/बाल संरक्षण संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा भरा जाए)
- 7 - हितग्राही के भाई/बहन की संख्या :
- 8 - हितग्राही की श्रेणी :
- 9 - हितग्राही की टीकाकरण स्थिति :
- 10 - परिवार नियोजन के ब्यौरे.....(प्रथम बालिका के लिए लागू नहीं)
- 11 - माता पिता/ हितग्राही का आधार नम्बर :
- 12 - आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम :
- (क) ग्राम :
- (ख) खण्ड/परियोजना :
- (ग) तहसील :
- (घ) जिला :

- 13 - वह कालावधि जिसके दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत हो।
 14 - क्या माता तथा पिता आयकर दाता है.....(हां/नहीं)
 15 - क्या बीपीएल कार्ड धारक है..... (हां/नहीं)
 16 - परिवार नियोजन प्रमाण पत्र माता पिता में से एक का.....(प्रमाणिक व्यक्ति/संगठन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न कीजिए) (प्रथम बालिका के लिए लागू नहीं)

घोषणा

- अ. मैं आत्मज और मैं पत्नी एतद्वारा सत्यापित करता हूँ / करती हूँ कि मैं/ हम आयकर दाता नहीं हूँ/ हैं। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि आवेदन की समस्त अंतर्वस्तुएं मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में सत्य हैं, यदि कोई भी जानकारी असत्य या झूठी पाई जाती है तो मैं/हम व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ/हैं और ऐसा पाए जाने पर समस्त लाभ सरकार के पक्ष में समर्पित कर दूंगा/देंगे।
- ब. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने कोई भी आवेदन किसी अन्य आंगनवाड़ी केन्द्र में या किसी लोक सेवा केन्द्र में या ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण या अपनी पुत्री का नाम हितग्राही के रूप में मैंने रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं किया है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि,-

(एक) बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पूर्व अनुष्ठापित नहीं किया जाएगा। (इस संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाए)

स्थान:-

तारीख:-

आवेदकों के हस्ताक्षर

(1)

(2)

पूरा पता

संलग्न दस्तावेज:

1. जन्म प्रमाण-पत्र.....(दस्तावेज संलग्न करें)
2. मूल निवास प्रमाण-पत्र। (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पहचान, यदि कोई हो, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र)
3. आंगनवाड़ी केन्द्र में रजिस्ट्रीकृत होने पर पर्यवेक्षक/प्रभारी आंगनवाड़ी केन्द्र का सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक है।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान

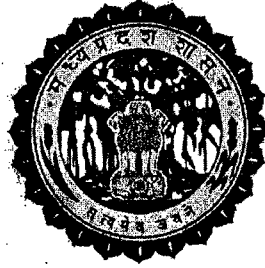
पूरा पता

लाइली लक्ष्मी योजना
(हितग्राही के माता-पिता को दी जाने वाली प्रतिलिपि)
प्ररूप-दो

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक :

दिनांक :.....



माता/ पिता के
साथ बालिका का
हाल ही का फोटो
चिपकाएं

आश्वासन प्रमाण-पत्र

लाइली लक्ष्मी योजना नियम 6 (3) के अधीन

लाइली कुमारीपुत्री श्रीमती और श्री
जन्म तारीखपताजिला.....

कुल रकम रूपए 1,18,000/-

- कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने के समय पर रूपए 2000/- (दो हजार रूपए)
- कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के समय पर रूपए 4000/- (चार हजार रूपए)
- कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने के समय पर रूपए 6000/- (छह हजार रूपए)
- कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने के समय पर रूपए 6000/- (छह हजार रूपए)

और

- 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रूपए 1,00,000/- (एक लाख रूपए) :

परंतु यह कि लाभ शासन द्वारा विहित आयु पूर्ण हो जाने के पश्चात् विवाह करने और कक्षा बारहवीं की परीक्षा में सम्मिलित होने के अध्ययधीन होगा।

लाइली सं

तारीख

स्वीकृतकर्ता अधिकारी
के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

स्वाबलम्बी बालिका - सशक्त समाज का आधार

**लाइली लक्ष्मी योजना
प्ररूप-दो (क)
(नियम 6 (3) देखिए)
कार्यालय सक्षम प्राधिकारी
आश्वासन प्रमाण-पत्र**

जिला.....

मैंने (बालिका) हितग्राही के पंजीयन के लिए आवेदन की अंतर्वस्तुओं को अच्छी तरह देख लिया है, जिसे प्रभारी आधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) तथा नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन अग्रेषित किया गया है ।

अ. मैंने यह विनिश्चित किया है कि आवेदन (हितग्राही का फोटो संलग्न है) पूर्ण रूप से ठीक है जिसे अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) तथा (3) के अधीन लाभ स्वीकृत करने के लिए हितग्राही के पक्ष में स्वीकार किया जाता है । अतः धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन आश्वासन प्रमाणपत्र हितग्राही के माता-पिता को एतद्वारा जारी किया जाता है ।

1.

2.

3.

या

मैंने यह विनिश्चित किया है कि पंजीयन तथा लाभ स्वीकृत करने के लिए आवेदन निम्नलिखित कारणों से निरस्त किए जाने योग्य है :-

(कारणों को अभिलिखित कीजिए)

1. =

2. =

3. =

ब. _____

प्रतिलिपि:

- (1) जिला कलेक्टर,
- (2) जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश

**स्वीकृतकर्ता अधिकारी
के हस्ताक्षर तथा मुद्रा**

लाइली लक्ष्मी योजना
प्ररूप-तीन
नियम 9 देखिए
हितग्राही के रजिस्टर का प्ररूप

अनुक्रमांक	हितग्राही पंजीयन क्रमांक	आवेदन प्राप्ति की तारीख	हितग्राही का नाम एवं वर्ग	हितग्राही के माता-पिता का नाम और पता	हितग्राही की जन्म तारीख	तारीख जिसको आश्वासन प्रमाणपत्र जारी किया गया है	समय-समय पर किए गए ई-पेमेंट की तारीख, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सत्यापित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

No. 2016-1264-2019-L-2.-

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 9 of the Madhya Pradesh Ladli Laxmi (Balika Protsahan) Adhiniyam, 2018 (No. 29 of 2018), the State Government, hereby, makes the following rules for the purpose of carrying out the Ladli Laxmi Yojna in the State of Madhya Pradesh, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Ladli Laxmi (Balika Protsahan) Yojna Rules, 2020.
- (2) These rules shall come in to force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Madhya Pradesh Ladli Laxmi (Balika Protsahan) Adhiniyam, 2018 (No. 29 of 2018);
 - (b) "Anganwadi centre" means a centre operated under the Integrated Child Development Project located in a village or ward of a district where the girl child is registered;
 - (c) "Anganwadi worker" means a person appointed at the concerned Anganwadi centre who has been authorized by the department for the purpose of receiving the application of the scheme in his/her survey area at the village / ward level;
 - (d) "Authorised officer" means the District Program Officer of the department of Women and Child Development who shall maintain an account of the deposits and dues in favour of the beneficiary girl;
 - (e) "Competent authority" means an authorized officer as specified in clause (c) of section 2 of the Act who shall be a child development project officer of the Department of Women and Child Development;

- (f) "Form" means the form appended to these rules;
- (g) "Officer in charge of registration centre" means an officer in charge of the Public Service Centre under the Public Service Guarantee Act, 2010 (No. 24 of 2010) or a person appointed to receive the application of the beneficiary for this purpose;
- (h) "Person-in-charge" means a person appointed for the control and management of the Child Care Institutions;
- (i) "Register of beneficiaries" means such register of beneficiaries in which the names of beneficiaries are registered and maintained in form-III by the authorised officer;
- (j) "Section" means the section of the Act;
- (k) "Supervisor" means the Person to supervise the aanganwadi centre concerned;
- (l) "Yojna" means Ladli Laxmi Yojna as specified in clause (h) of section 2 of the Act.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Eligibility of Yojna.-** A female child who is or has been registered as beneficiary under the Yojna shall be eligible for the benefits as specified in section 5 of the Act.

4. **Entitled for Registration as Beneficiary.-**

(1) Such parents will be eligible to register their girl's name as a beneficiary in the scheme, if –

(a) The girl child whose parents are native to the state of Madhya Pradesh will be entitled to avail the benefits of the scheme;

(b) The parents are not income tax payee at the time of registration;

Provided that if either mother or father or both have become income tax payee after the registration, the female child shall continue to get the benefits under the Yojna;

- (c) The first born girl child will be entitled to the benefits of the scheme, irrespective of whether her parents have adopted family planning or not but the condition of adopting family planning will be mandatory for the registration of the second girl child and in the case of birth of two or more girls in the first delivery, all the girls will be eligible.
- (d) The girl child should be enrolled in the nearest anganwadi center.
- (2) If the beneficiary is a girl child in need of care and protection (CNCP) no aforesaid conditions will be applicable for the beneficiary.
- (3) Eligibility for beneficiary registration in special cases.-
- (1) In the event of maximum of two children are in a family and either of the parents dies, the condition of adopting family planning shall not be applicable but submission of death certificate of the deceased person shall be a prerequisite criterion. In such cases, the girl child can be registered under the scheme up to the age of 05 years.
- (2) If a family has legally adopted a female child then the female child shall be entitled to the benefits of the yojna as a first girl child but the family should apply within one year from adoption or succession of child for registration.
- (3) If parents or one of them have not applied for registration under the scheme within one year by reason of medical ground then such parents may apply within two years from the birth of female child to the competent authority. The competent authority shall submit such applications to the Collector through the authorized officer for acceptance or rejection.
- (4) State Government shall have powers to sanction the time barred cases.
- (5) Where in a family twin girls are born after a male or female child, both the girls shall be eligible for benefits under the yojna.
- (6) The female child of the women prisoner who is confined in jail by whatever reason and gives birth a female child in jail shall also be entitled for the benefits under this yojna.

- (7) The girl child born by a rape victim will also be entitled for the benefits under the scheme.

5. Application for Registration.-

- (1) The parent shall submit an application in duplicate to the officer in charge of the registration center within one year from the birth or adoption of a female child in Form-I:

Provided that the application may also be submitted in Form-I at the Lok Seva Kendra or through Ladli Laxmi Yojna website (www.ladlilaxmi.mp.gov.in) of the department.

- (2) The following information shall be required to be furnished at the time of submission of the application under the Yojna: -

- (a) proof of bona fide resident of the parents;
- (b) birth certificate of the girl child;
- (c) Authentic proof of adopting family planning in the case of second child;
- (d) Proof of enrolment at aanganwadi Centre;
- (e) Self-statement regarding non income tax payee;
- (f) Proof of residence of orphanage;
- (g) Proof of adopted female child by adoptive parents.

- (3) The-In-charge of the jail or orphanage or child care institution shall have to apply for registration of the female child beneficiary within one year but before her attaining the age of five years from the date of entering or admitting the female child in such orphanage or child care institution.

6. The Registration process.-

- (1) On receipt of the application, the officer in-charge of the registration center or aanganwadi worker shall verify the contents of the application, register the same and provide the serial number and the duplicate copy shall be returned to the applicant. Thereafter, he shall forward it to the competent authority for issuing the assurance certificate.

- (2) On receipt of the application, the competent authority shall either issue the assurance certificate in Form-II or reject the application with the reasons being recorded in writing and intimate the parents of the female child. The competent authority shall dispose of the application within one month from the date of filling it. The competent authority shall send its report in Form-II (A) within the period of two month to the authorized officer containing the numbers of issuing assurance certificate and the applications rejected by him with sufficient reasons.
- (3) After issuance of assurance certificate, the sum of thirty thousand rupees shall be deposited by such authorized officer on behalf of Government who shall be authorized by WCD. Such officer shall maintain the proper account and its report shall be sent to the commissioner, Women & Child Development Deptt. through collector every year.
- (4) A register of beneficiary shall be maintained and kept in the safe custody of the authorized officer in proforma given in form-III. Apart from this, information in this regard shall also be maintained on the website (www.ladlilaxmi.mp.gov.in) of the scheme.

7. Appeal.-

- (1) If the application is rejected or not disposed of within the time limit, an appeal may be filed as follows-
 1. First appeal - The District Program Officer, Women and Child Development Department shall be the first appellate officer. The deadline for disposal of appeals will be 15 working days.
 2. Second appeal- The second appeal against the order of the first appellate officer will be presented before the District Collector.

8. Cancellation of registration.-

- (1) After the registration in the scheme, if the said contents in the application are found to be untrue or false in the investigation, then such registration can be cancelled by the competent officer and after cancellation all the benefits are deemed to be passed on to the government but before

cancelling the registration, it will be necessary to give the applicant a reasonable opportunity of hearing.

- (2) In case of child marriage of the registered girl child, the registration in the scheme shall be deemed to be cancelled automatically and action can be taken under the Prohibition of Child Marriage Act, 2006.
- (3) On the death of the registered girl, all the benefits shall be deemed to have been transferred to the State Government.
- (4) If such who are registered under Ladli Laxmi Yojana and resides the child care institutions, are adopted by natives from abroad or other states the registration Ladli Laxmi scheme of these girls shall be revoked after 2 years from the date of order of the Court. But the benefit of the scheme to the girl child adopted by the native family of the state will continue.
- (5) All documents related to cancelled cases will be maintained on the scheme portal <https://ladlilaxmi.mp.gov.in>

9. Entitlement of benefits.-

- (1) Every female child registered under the Yojna shall be entitled for a sum of Rs. 1,18,000/- (one lakh eighteen thousand Rupees) only as below: -
 - (i) At the time of admission to class 6th Rs. 2000/- (Rs. Two thousand) only.
 - (ii) At the time of admission to class 9th Rs. 4000/- (Rs. four thousand) only.
 - (iii) At the time of admission to class 11th Rs. 6000/- (Rs. six thousand) only.
 - (iv) At the time of admission to class 12th Rs. 6000/- (Rs. six thousand) only.
 - (v) At attaining age of 21 year Rs. 1,00,000/- (Rs. One lakh) only.

Provided that while receiving the benefits under clause one to four the information of the girl's admission in the current class along with the mark-sheet of the previous class will be collected necessarily:

Provided further that it shall be mandatory for the girl child to appear in the class 12th examination to get the benefit under clause five, and a mark sheet of class 12th will have to be submitted:

Provided further also that in case of married beneficiary, marriage registration certificate will also be submitted.

- (2) Payment for the scheme will be made from the Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojana fund (NIDHI) budget as set aside by the Women and Child Development Department for the beneficiary.
- (3) The sum stated in assurance certificate shall be paid in the account of beneficiary only through E- Payments.
- (4) If the female child does not fulfill the prescribed eligibility condition or has died then all benefits shall be deemed to be forfeited to the State Government.
- (5) The Pecuniary benefit accrued to the beneficiary under sub-section (2) and section 5 of the Act shall be of the permanent nature and shall not be recovered but the final benefit shall be depending on the eligibility of the girl child specified in the Act.
- (6) Under this Yojna, the mother of the beneficiary shall be the guardian and in case of death of the mother, the father shall be the guardian and if mother and father both have died then her legal guardian shall be appointed by the Collector who shall not be below the rank of Deputy Collector or District Programme Officer, Women and Child Development Department and in case of the orphanage or Child Care Institution, the Superintendent shall be the legal guardian where orphan female child is admitted.
- (7) Priority will be given to eligible candidates for various employment oriented schemes and admission in professional courses run by the state government.

10. Maintenance of Ladli Laxmi Yojna Nidhi.-

- (1) The State Government shall constitute and maintained a fund which shall be known as Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojna Nidhi which shall be utilized for disbursing pecuniary benefits to the beneficiary.
- (2) The fund shall be constituted by the following: -
 - (i) A sum of Rs. 30000/- (Thirty Thousand Rupees) shall be deposited by District Programme Officer, Women and Child Development Department on behalf of the State Government in the fund for each beneficiary after her registration; and

- (ii) The matured sums of National Saving Certificate with interest, if any, issued by the postal department deposited by the women and child Development Department;
 - (iii) Apart from this, to settle the claims of the beneficiaries the amount will be reimbursed by the state government and transferred to the fund, if needed in the fund.
- (3) Secretary, Department of Finance and Director, Institutional Finance will be the members in the Standing Committee constituted under the chairmanship of Principal Secretary, Women and Child Development. Commissioner, Women and Child Development will be the member secretary in the committee. The committee will conduct meetings to review the fund (NIDHI).

11. Maintenance of Record of the beneficiaries.-

- (1) A register relating to the beneficiaries under the scheme shall properly be maintained by the authorized officer and proper records of beneficiaries shall be kept in the register prepared therefore. Apart from this all documents will be maintained on the portal (www.ladlilaxmi.mp.gov.in) of the scheme.
- (2) When an assurance certificate is issued to the beneficiary, the details of which shall be registered and second copy of assurance certificate shall be kept in a safe custody of the office of the authorized officer. The certificate of assurance can be downloaded from the portal (www.ladlilaxmi.mp.gov.in) of the scheme.
- (3) Every beneficiary shall be given an enrolment number from the scheme portal (www.ladlilaxmi.mp.gov.in) and the entry shall be made in the register kept for this purpose.
- (4) As and when the payment is made to the beneficiary, its entry should be recorded in the register and scheme portal (www.ladlilaxmi.mp.gov.in) against the name of beneficiary with the date on which the amount is paid by E-payment.

12. Monitoring and evaluation.-The monitoring and evaluation of the scheme shall be made in following level:-

- (1) **At the district level.-**

- (a) The authorized officer (District Program Officer), Women and Child Development Department will be responsible for monitoring. If necessary, he will also evaluate all such matters under the scheme which have been decided by the competent authority (Child Development Project Officer) and he will also send the report to the Collector from time to time.
- (b) After receiving the report from the District Program Officer of Women and Child Development Department, the Collector will review the report. The District Program Officer will report the difficulties, suggestions and recommendations (if any) regarding the scheme to the Commissioner, Women and Child Development Department.
- (c) The decision of the District Collector will be final if a dispute arises regarding registration / benefit of the beneficiary at the district level under Section 8 of the Act.

(2) At the division level.-

The Divisional Joint Director, Women and Child Development Department will visit the planning records of the subordinate office of the District Program Officer and the Office of Child Development Project Officer in the inspections conducted from time to time. Also he will be able to give instructions for necessary corrective action in relation to plan implementation and record maintenance.

(3) At the state level.-

- (a) If any discrepancy is found regarding the implementation of the scheme, the head of the department will send its recommendation to the state government to rectify the discrepancy.
- (b) In case of any dispute or discrepancy arising in the implementation of the scheme at the state level, the decision of the head of the department, Women and Child Development Department will be final.

13. Directions by State Government.-

- (1) The state Government may issue such directions from time to time for appropriate implementation of the yojna made under the Act and the rules, as it may think proper.
- (2) The fund shall be kept separately by making provision in budget in year to year for all female children registered during the period of 1st April 2007 to the commencement of this Act under the yojna as beneficiary.

14. Validation of the Proceedings.-

All the proceedings made under administrative orders relating to the Madhya Pradesh Ladli Laxmi Yojna of the State Government prevailing at present as begins from 1st April, 2007 and upto the commencement of this act and rules made thereunder, shall be deemed to be validated under the provisions of the act:

Provided that any action taken or order issued or made under the Ladli Laxmi Yojna prior to the notification of these rules, in so far it is not inconsistent with the provisions of the act and rules made there under, deemed to have been taken or issued or made under shall be the provisions of these rules .

- 15. Non- compliance of the Act and the rules.-** If any officer/institution or statutory body etc. who is responsible for registration and for providing pecuniary and other benefits of the scheme fails to comply with the provisions of the act and the rules framed there-under, the state Government may take action against such officer/ institution or statutory body etc. after due inquiry who is responsible or who is found negligent for effective implementation of the scheme under the Act.

16. Information, Education and Communication: -

The objectives of the Act will be fulfilled by the state government through street plays, slogans, brochures, posters, electronic media, print media, training programs, etc. at certain intervals to change the social behavior of the community.

- 17. On the consent of the girl child, she can be linked with the opportunities of self-employment. For this, the amount received by the beneficiary of Ladli Laxmi Yojana on 21 years can be used as margin money in various**

government schemes or bank loans operated by the state government for economic empowerment. The economically strong girl child registered under the scheme will be able to set exemplary examples for the society, to eliminate the malpractices of believing the girl child as financial burden and the dowry system as well. The basic objective of Ladli Laxmi Yojana is to provide equal opportunities to girls for education and encourage them to become financially strong.

18. Social audit: -

In the context of accomplishing the objectives mentioned under the Act, the state government will conduct social audit through local bodies and social organizations. The social audit shall consist the following points :-

1. Changes in perception towards daughters in the society due to Ladli Laxmi Yojana.
2. Increase in sex ratio
3. Family to adopt family planning.
4. Abolition of female feticide and female childbirth.
5. To increase the school enrollment ratio of girls.
6. To increase enrollment of girls in higher and professional education.
7. End of dowry practice.
8. Economic empowerment of girls, i.e. increasing participation in the workforce.

Form-I
Ladli Laxmi Yojna
[See Rule 3 and rule 4 (1)]
(Beneficiary Registration form to be filled in duplicate)

Application form for registration of the beneficiary under Ladli Laxmi Yojna (to be filled in by parent / legal guardian / superintendent/ person in charge of child care institution)

To,

The Officer incharge of Registration center
Competent Authority
Block /Integrated Child Development Project
Tehsil-----
District -----
Madhya Pradesh

To be affixed recent
photo of female child
with the mother/father

Sir,

I desire to register my daughter as beneficiary of the Ladli Laxmi Yojna, the details are as under: -

- 1- Name of Female Child:
- 2- Name & Age of Mother :
- 3- Name & Age of father :
- 4- Occupation & annual income of family :
- 5- Residential address with pin code & mobile number :
- 6- (i) Date of Birth of Female Child (Certificate to be attached) –
(ii) Date on which female child entered in the Jail/child care institution. (To be filled in by person in charge Jail/Child care institution)
- 7- Number of siblings of the beneficiary:
- 8- Category of Beneficiary :
- 9- Vaccination Status of Beneficiary:
- 10- Family Planning Detail (Not applicable for the first girl child)
- 11- Aadhar number of Parents/Beneficiary:
- 12- Name of Aanganwadi Centre:
 - (a) Village
 - (b) Block /Project
 - (c) Tehsil
 - (d) District
- 13- Period during which residing in area of Aanganwadi centre.

- 14- Whether the Parents are income tax payee(yes/no)
 15- Whether holding BPL card(yes/no)
 16-Family planning certificate belongs to one of the parents
 (Attach certificate issued by the authentic
 person/organization) (Not applicable for the first girl child)

Declaration

A. I,..... s/o.....and I.....

W/o..... do hereby, certify that I/we
 am/are not Income Tax payer. I/we also certify that all
 contents of the applications are true to the best of my
 knowledge and belief, if any information is found false or
 untrue, I/we shall be personally responsible and shall
 surrender all benefits in favour of Government.

B. I also certify that I have not submitted any application to
 any other Aanganwadi Centre or any Lok Seva Kendra or
 online registration or registration of my daughter's name as
 beneficiary.

I also declare that,-

- (i) The marriage of the female child shall not be solemnized
 or performed before attaining the age of 18 years.
 (Affidavit should be filed in this regard)

Place:

Signature of the applicants

(1) -----

(2) -----

Date:

Full Address.....

Attached Document:

1. Birth certificate..... (document attached)
2. Domicile residence certificate. (ration card, voter card, identity if any and certificate issued by competent authority)
3. On being registered with the Aanganwadi centre the verification certificate is necessary of the supervisor/In-Charge of the Aanganwadi centre.

Place:-

Signature or thumb impression of the applicant

Date:-

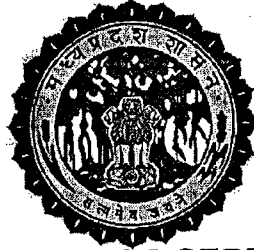
Full Address.....

Ladli Laxmi yojna
(Copy to be given to the parent of the beneficiary)
Form-II

Government of Madhya Pradesh
Women and Child Development Department

No

Date



ASSURANCE CERTIFICATE

Under LADLI LAXMI YOJNA rule 6(3)

Ladli Ku. ----- D/o Smt..... & Shri.....

Date of Birth -----

Address----- District -----

To be affixed
recent photo of
female child
with the
mother/father

Total sum Rs. 1,18,000/-

the time of admission to class 6th Rs. 2000/- (Rupees Two
Thousand)

- At the time of admission to class 9th Rs. 4000/- (Rupees Four
Thousand)
- At the time of admission to class 11th Rs. 6000/- (Rupees Six
Thousand)
- At the time of admission to class 12th Rs. 6000/- (Rupees Six
Thousand)

and

- At the time of attaining age of 21 years Rs. 1,00,000/- (Rs. one lakh) :
Provided that this benefit shall be subject to marrying after attaining
age prescribed by the Government and participating in examination of
class- XIIth.

Ladli No. -----

Date -----

Signature and seal
of
Sanctioning Officer

Ladli Laxmi Yojna
Form-II(A)
[See rule 6(3)]
OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY
Assurance Certificate

District-----

I have gone through the contents of application for registration of beneficiary (Female child) which has been forwarded by the officer-in-charge under sub rule (1) of rule 5 and subsection (2) of section 4 of the Act.

A. I have decided that the application (photograph of beneficiary is enclosed) is complete in all respect and is accepted in favour of the beneficiary for sanctioning benefit under sub-sections (2) and (3) of section 5 of the Act. Therefor the assurance certificate is hereby issued to the parent of the beneficiary under sub-section (3) of section

4.

1.

2.

3.

or

I have decided that the application for registration and sanctioning benefit deserves to be rejected on the following reason: -

(Reasons to be recorded)

1. =

2. =

3. =

B. _____

Copy

1. **District Collector,**

2. **District Programme officer, Women & Child Development Deptt.**

M.P.

Seal & Signature of
the Sanctioning officer

Ladli Laxmi Yojna**Form-III****(See rule 9)****PROFORMA OF THE REGISTER OF BENEFICIARY**

S. No	Beneficiary Registration Number	Date of receipt of application	Name & Category of beneficiary	Name and address of parents of beneficiary	Date of birth of beneficiary	Date on which Assurance Certificate is issued	Date of E-payment made for time to time attested by the District programme officer women child development department
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Seal and Signature of
the Authorised officer

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना मेहरा अटूट, उपसचिव.